Demand to fulfil various needs pertaining to rail network in the State of Tripura

SHRI MATILAL SARKAR (Tripura): Sir, the conversion work of metre gauge to broad gauge is a long due task of the Railway authorities in the North-East, where about half the length comprises of metre gauge lines. The entire line to Tripura is of metre gauge. The conversion works in the Lumding-Badarpur sector have been badly affected on account of insurgency in that part of Assam. As the problems of insurgency are not merely law and order problems, the Central Government should come to the help of the concerned State. Conversion work cannot wait. I invite the attention of the Central Government to this acute problem. Secondly, there is a heavy pressure of passengers on the railway line between Agartala and Dharmanagar in Tripura. There is a tremendous demand for starting a train from Agartala to Dharmanagar in the morning and return in the evening. This is the high time to implement this. I would request the Central Government to concede to this genuine demand.

Thirdly, the works of extension of railway lines from Agartala to Sabroom have not yet started. This needs more care and attention.

Fourthly, Agartala and Kolkata may be well connected by rail through Bangladesh. What is needed is a segment of railway line of 13 kilometres from Agartala to the nearest railway station in Bangladesh. The matter should be taken up with Bangladesh at appropriate level. It is needless to say that both the countries will be benefited by this. I urge upon the Central Government to give due importance to the four issues raised above and take suitable steps as matters of priority.

Demand to include people belonging to Rajvanshi community in the list of Scheduled Tribes

श्री तारिक अनवर (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित मामले की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं:

राजवंशी समुदाय (जाति) के लोग बिहार राज्य के कटिहार जिले में काफी तादाद में रहते हैं। इनकी भाषा, रहन-सहन, वेष-भूषा और अन्य पारम्परिक रीति-रिवाज पश्चिमी बंगाल राज्य में रहने वाले राजवंशी समुदाय (जाति) के समान ही हैं। पश्चिमी बंगाल राज्य में राजवंशी समुदाय (जाति) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा मिला हुआ है, जबकि बिहार राज्य में अभी तक राजवंशी समुदाय (जाति) को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण इस समुदाय के लोग अनुसूचित जनजाति (एसटी) को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राजवंशी समुदाय (जाति) को बिहार में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल किए जाने के लिए बिहार सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को कोई पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है? यदि केन्द्र सरकार को बिहार सरकार द्वारा राजवंशी समुदाय (जाति) को बिहार में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सूची में शामिल किए जाने संबंधी कोई अनुशंसा-पत्र प्राप्त हुआ है तो केन्द्र सरकार ने अब तक उस पर क्या कार्यवाही की है अथवा करने पर विचार कर रही है? धन्यवाद।

Need to take effective measures to check the infiltration of Bangladeshis in the country

श्री श्रीगोपाल व्यास (छत्तीसगढ़): महोदय, एक रिपोर्ट के अनुसार बंगाल में 80 लाख, असम में 55 लाख, त्रिपुरा में 4 लाख व बिहार में 5 लाख बंगलादेशी घुसपैठिये हैं। इससे जनसंख्या संतुलन अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि उत्तर पूर्व में काम कर रहे 20 से अधिक आतंकवादी संगठन प्रशिक्षण व सहायता

बंगला देश से प्राप्त करते हैं। इन घुसपैठियों ने दारंग एवं उजालगुड़ी जिलों में मंगलदोई सहित 40 गांवों में आग लगा दी थी। फलतः 80,000 लोगों को कैम्पस में रहना पड़ा था। पाकिस्तानी झंडे लगाए गए व पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे भी लगाए गए। जून, 2008 में गोहाटी उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण स्थिति के गंभीर परिणामों की ओर इंगित किया था। अवैध घुसपैठियों के द्वारा संख्या के बल पर सत्ता पर काबिज़ होने की आशंकाएं भी हैं।

महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अत्यधिक आग्रह करता हूं कि वह इन घुसपैठियों को पहचान के लिए कुछ योरोपीय देशों में अपनाये जा रहे तरीकों सहित अन्य उपाय करे, मतदाता सूची में से उनके नाम हटाए, उन्हें वापिस भेजें, शरण देने वालों पर कार्रवाई करे और अधूरी बाड़ को शीघ्रताशीघ्र युद्ध स्तर पर पूरा करे और सुनिश्चित करे कि फिर कोई घुसपैठ नहीं होगी। धन्यवाद।

श्री रुद्रनारायण पाणि (उड़ीसा) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भागीरथी माझी (उड़ीसा) : महोदय, मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री भारतकुमार राऊत (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं भी इससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

श्री रघुनन्दन शर्मा (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं भी इससे एसोसिएट करता हूं।

Demand to establish centre for Similipal studies under the North Orissa University

MS. SUSHILA TIRIYA (Orissa): Sir, a draft proposal has been submitted by the North Orissa University to the Ministry of Environment and Forests to establish a Centre for Similipal Studies under the university near Jashipur, at the foothill of Similipal Biosphere Reserve. As a matter of fact, the Similipal Biosphere Reserve is a huge natural property of the country which needs in-depth studies. The Centre will cater to the needs of the people, researchers, visitors, tourists as well as five lakh inhabitants inside the core and buffer areas.

It is a unique God-gifted nature of beauty which later on constituted four units, namely, Similipal Wildlife Sanctuary constituted on 2306.61 kilometre; Similipal National Park constituted on 845.70 kilometre; Similipal Tiger Reserve constituted on 2,750 kilometre, and, the Similipal Biosphere Reserve constituted on 5,569 kilometre. According to the research conducted by different organisations, huge existence of limonite, bauxite, more than one crore tonnes of diesel, gold, platinum and mercury at Nauna, Gudgudia and Billpagha has been found.

The enormous forest resources will also enhance the socio-economic status of the ethnic people as well as eco-tourism aspects.

The study can be the milestone for the upliftment of the tribals of Orissa in general and Districts of Mayurbhanj and Keonjhar, in particular. I, therefore, urge upon the Government to establish the Centre of Similipal Studies under the North Orissa University at the earliest.

Need for an inquiry into the reported irregularities in the import of aircraft carrier Admiral Gorshkov

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सी.ए.जी. ने अपनी एक ताजा रिपोर्ट में एक गम्भीर मामले का खुलासा किया है। यह वित्तीय अनियमितताओं एवं अक्षम्य विलम्ब का एक ऐसा मामला है, जिसे जानकर सम्पूर्ण देश की जनता आश्चर्यचकित है। सन् 2004 में भारत सरकार ने रूस से एक पुराना second hand